20 लाख एमएसएमई, 10 लाख पटरी दुकानदारों को देंगे कर्ज

सीएम ने **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना** के लाभार्थियों को बांटे टूल किट और मुद्रा लोन

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एमएसएमई की 20 लाख इकाइयों को लोन बांटा जाएगा। वहीं, केंद्र के आर्थिक पैकेज के तहत प्रदेश के 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ा जाएगा। इसके लिए लक्ष्य तय करते हुए कार्ययोजना बनाएं। कोविड के मानकों का पालन करते हुए सभी आर्थिक व विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए।

सीएम ने गुरुवार को देवशिल्पी विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को टूल किट और मुद्रा लोन वितरित किया। कुछ लाभार्थियों से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत की। योगी ने कहा कि अर्थव्यवस्था और समाज के लिए जरूरी हस्तशिल्पियों, कारीगरों व अन्य पारंपरिक उद्योगों से जुड़े लोगों को सरकार ने समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है। पहले यह लोग उपेक्षित थे। उनके पास हुनर था, लेकिन मंच नहीं था। कौशल था, लेकिन प्रोत्साहन नहीं था। 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' व ओडीओपी ने इन्हें मंच दिया। वित्तीय समावेश के साथ कारीगरों व हस्तशिल्पियों को जोड़े जाने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। योजना में भड़भूजा, धोबी व शिल्पकार की नई श्रेणी भी जोड़ी गई है।

जो भी आवेदन करे उसे मिले लोन

योगी ने कहा कि प्रशिक्षण एवं टूल किट प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे अपना व्यवसाय स्थापित करते हुए अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकें। योजना के तहत जितने भ आवेदन आएंगे, उन सभी को मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाया जाए। बैंक हर जिले में एमएसएमई व ओडीओपी के लिए लक्ष्य तय कर लोन वितरित करें। हस्तशिल्पियों व कारीगरों को डिजिटल पेमेन्ट के साथ जोड़ा जाए। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि पीएम मुद्रा योजना के तहत बड़ी संख्या में विभिन्न ट्रेडों से जुड़े लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह व विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

विश्वकर्मा सम्मान योजना एक नजर में

1.12 लाख आवेदन आएं हैं प्रशिक्षण के लिए	**20** हजार आवेदकों का प्रशिक्षण पूरा	**2,000** प्रवासी कारीगर भी किए गए प्रशिक्षित	**4,500** प्रशिक्षित कारीगरों को 60 करोड़ का मिला ऋण

'बनेंगी आठ ग्रीनफील्ड डेयरी'

सीएम ने उन्नाव और हरदोई के चार दुग्ध उत्पादकों को दिए बोनस के चेक

■ एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादन के जरिए गांवों की अर्थ व्यवस्था मजबूत करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए अधिक से अधिक राजस्व गांवों में दुग्ध समितियों का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में यहां 7,293 दुग्ध समितियां कार्यरत हैं, जिन्हें बढ़ाने का कार्य लगातार चल रहा है। कहा कि सरकार प्रदेश में आठ ग्रीनफील्ड डेयरियों की स्थापना करा रही है। यह ग्रीनफील्ड डेयरियां लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या और मुरादाबाद में स्थापित की जा रही हैं। इसके साथ ही झांसी, नोएडा, अलीगढ़ और प्रयागराज की चारों पुरानी डेयरियों के आधुनिकीकरण का काम भी कराया जा रहा है।

सीएम गुरुवार को अपने आवास पर गुजरात की बनास डेयरी द्वारा यूपी के दुग्ध उत्पादकों के बोनस भुगतान को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी होने के साथ ही, अमूल की सबसे बड़ी सदस्य है। बनास डेयरी ने करीब 30 करोड़ रुपये बोनस के रूप में किसानों को अतिरिक्त रूप से देना तय किया है। यह

कुल खरीद का 4.41 प्रतिशत है। यह धनराशि बनास डेयरी द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इस मौके पर सीएम ने उन्नाव और हरदोई जिलों के दो-दो दुग्ध उत्पादकों को बोनस के चेक भी प्रदान किए। साथ ही कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनास डेयरी को दुग्ध की आपूर्ति करने वाले बिजनौर, वाराणसी, फतेहपुर, जालौन, आगरा और कानपुर देहात के एक-एक किसान से बातचीत की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित इस बोनस वितरण कार्यक्रम के लिए सीएम ने बनास डेयरी का आभार जताया।

कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से बनास डेयरी के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी और गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी आरएस सोढ़ी ने भी संबोधित किया।